



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण 1944 (श10)
(सं0 पटना 1095) पटना, मंगलवार, 20 दिसम्बर 2022

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
8 सितम्बर 2022

सं० 22/नि0सि0(औ0)17-09/2017/2180—श्री संजय रमण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0डी0-3365) सोन नहर प्रमण्डल, खगौल द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा कि गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर कि गई। सम्यक समीक्षोपरांत निम्न आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक-65 दिनांक-14.02.17 द्वारा श्री रमण से स्पष्टीकरण किया गया:-

आरोप—

- (i) विभागीय भूमि पर अवैध रूप से सामुदायिक भवन के निर्माण की सूचना सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रेम प्रकाश द्वारा दायर परिवाद द्वारा विभाग को दिनांक-02.02.16 को प्राप्त हुई उक्त अवैध निर्माण के प्रति आपने कोई संज्ञान नहीं लिया तथा इसके विरुद्ध आपके स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
- (ii) उक्त अवैध निर्माण की सूचना आंशिक रूप से अधीक्षण अभियंता को काफी विलंब से पत्रांक-291 दिनांक-18.02.16 द्वारा दी गई।
- (iii) आपने विभागीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य बंद कराने को जो पत्रांक-1525 दिनांक-23.09.14 स्थानीय थाना को प्रेषित किया है उसमें भूमि की विवरण का अभाव है।
- (iv) अवैध निर्माणाधीन भूमि के भूस्वामित्व संबंधी साक्ष्य नगर परिषद द्वारा पत्रांक-342 दिनांक-06.04.16 द्वारा मांगने पर भी ठोस साक्ष्य आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री संजय रमण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का मुख्य अंश:-

श्री रमण द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया कि अवर प्रमंडल पदाधिकारी नौबतपुर के पत्रांक-24 दिनांक-08.02.18 द्वारा मामले की जानकारी उन्हें दी गई। तत्पश्चात, अंचलाधिकारी, दानापुर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, खगौल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर, अनुमंडलाधिकारी, दानापुर एवं थाना प्रभारी, खगौल से अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया। साक्ष्य के रूप में दिनांक 09.02.16 से दिनांक-04.07.16 तक निर्गत विभिन्न पत्रों का उल्लेख किया गया है।

श्री रमण ने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि प्रमंडलीय पत्रांक-254 दिनांक-11.02.16 जो कार्यपालक अभियंता उड़नदस्ता प्रमंडल सं0-04 अनिसाबाद, पटना को संबोधित हैं, की प्रति अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को भी

प्रेषित की गई। प्रमंडलीय कार्यालय में जमीन संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की बात का उल्लेख श्री रमण द्वारा किया गया।

उडनदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, श्री रमण के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं श्री रमण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण कि समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि अवैध रूप निर्माण कराये जा रहे सामुदायिक भवन की सर्वप्रथम सूचना विभाग को परिवादी से प्राप्त हुआ। जबकि कार्यपालक अभियंता श्री रमण द्वारा अतिक्रमण संबंधी सूचना पूर्व में ही विभाग को दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। जबकि अतिक्रमण भूमि कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के समीप है एवं पूर्व में भी जल मीनार का निर्माण अतिक्रमण कर किया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगौल से केशर-ए-हिन्द भूमि जल संसाधन विभाग का है, का दावा करते हुए उन्हीं से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करनी चाहिए थी एवं इसकी सम्पुष्टि अंचलाधिकारी से भी करानी चाहिए थी जो नहीं की गई।

प्रमंडल में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर कार्यपालक अभियंता द्वारा नगर परिषद के पत्रांक-115, दिनांक-18.03.2009 एवं विभागीय पत्रांक-1362 दिनांक-13.08.1991 की जानकारी पहले ही नगर परिषद, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, एवं अन्य अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया।

विभागीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किये जा रहे सामुदायिक भवन के संबंध में खगौल थाना में देर से सूचना दिये जाने एवं विधिवत् प्राथमिकी नहीं दर्ज कराने के लिए श्री रमण उत्तरदायी पाये गए।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगौल के द्वारा निर्माण कराये जा रहे सामुदायिक भवन जमीन से संबंधित/भू स्वामित्व से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग कार्यपालक अभियंता से की गई थी। इस संदर्भ में सोन कांडा को विषयांकित भूमि 10 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित करने हेतु विभागीय स्वीकृति को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में नहीं प्रस्तुत करने के लिए कार्यपालक अभियंता श्री संजय रमण उत्तरदायी पाये गए।

जल मीनार निर्माण के पश्चात् बचे हुए भू भाग जिसपर नगर परिषद द्वारा अवैध रूप से सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण किया जा रहा था, को धेराबंदी कर भविष्य में होने वाले अतिक्रमण से बचाने हेतु श्री रमण द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में कृषि हेतु नहर चाट की बन्दोवस्ती नहीं किये जाने के फलस्वरूप विभाग को राजस्व की हानि हुई। जिसके लिए श्री संजय रमण उत्तरदायी पाये गए।

इस प्रकार श्री रमण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रमण के विरुद्ध "निन्दन की सजा एवं एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजय रमण तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, खगौल को विभागीय अधिसूचना सं0-1602 दिनांक 29.07.2019 द्वारा निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया गया -

(i) निन्दन की सजा।

(ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्ड के आलोक में श्री रमण द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित की गई, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री रमण द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में उसी बात को पुनः दोहराया गया है जिसका वर्णन पूर्व में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में अंकित है। उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री रमण के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजय रमण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (आई0डी0-3365) सोन नहर प्रमण्डल, खगौल के विरुद्ध अधिसूचना सं0-1602 दिनांक 29.07.2019 द्वारा संसूचित दण्ड को बरकरार रखते हुए श्री रमण द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार किया जाता है।

उक्त आदेश श्री रमण को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1095-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>